विधानसभा सत्र दिसम्बर 2025 के विधान सभा
अतारांकित प्रश्न क्र 30 के प्रश्नांश "क" की जानकारी
सदस्य - श्री चिंतामणी मालवीय बैठक दि. 01/12/25

परिशिष्ट का प्रपत्र

मानीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारतसरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में खोले गये नवीन आयाम के संबंध में मध्यपदेश में की गई कार्यवाही की जानकारी।

1. **पैक्स कम्प्यूटराईजेशन**

वित्तीय वर्ष 2023-24 पर समस्त 4536 पैक्स में सॉफ्टवेयर आधारित अंकेक्षण पूर्ण। पैक्स को रियलटाइम आधार पर सॉफ्टवेयर पर कार्य करने हेतु संवेदनशील बनाते हुए प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि आगामी वर्ष से इन्हें ई-पैक्स मोड में लाया जा सके।

2. **नवीन पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी संस्थाओं का गठन-**

प्रदेश में प्रत्येक ग्राम किसी न किसी पैक्स के कार्य क्षेत्र में होने से नवीन एम-पैक्स का गठन किये जाने हेतु वर्तमान संस्थाओं का पुर्नगठन किया गया हैं। 629 नवीन एम-पैक्स, 726 नवीन डेयरी संस्थाओं एवं 199 नवीन मत्स्य सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया है।

3. **एनसीडी पोर्टल पर प्रविष्टि**

प्रदेश में 54538 पंजीकृत सहकारी संस्थाओं की जानकारी की प्रविष्टि एनसीडी पोर्टल पर की जा रही है। संस्थाओं की आधार भूत जानकारी तथा सदस्यता संबंधी जानकारी की प्रविष्टि सत् प्रतिशत की जा चुकी है।

4. **विश्व की सबसे बड़ी अनाज भण्डारण योजना**

प्रदेश में आरकेव्हीवाई तथा अन्य योजनाओं में शत-प्रतिशत अनुदान से पैक्स में प्रर्याप्त भण्डारण क्षमता विकसित हो गई हैं।

5. **प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र (PMJAK)**

प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र के लिये 271 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा आवेदन किया गया हैं, जिसमें से 83 संस्थाओं को
प्रशासनिक अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका हैं।

6. **कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC)**

प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स) अब कॉमन सर्विस सेन्टर की तरह कार्य कर रही हैं। पैक्स में अब किसान सिर्फ कृषि संबंधित सेवायें के अलावा डिजीटल और सहकारी ऑन लाइन सेवा भी प्राप्त कर रहे हैं।

7. **प्रधानमंत्री किसान समृदिध केन्द्र (PMKSK)**

किसानों के लिए "वन-स्टॉप शॉप" की तरह काम करते हैं, जहाँ उन्हें खेती से जुड़ी सभी

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग

ज़रूरतें जैसे कि उर्वरक, बीज और कीटनाशक मिलते हैं। इसके अलावा, ये मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, कृषि विशेषज्ञ परामर्श और आधुनिक तकनीकों की जानकारी जैसी सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं।

8. <u>सहकारिता में सहकार</u>

"सहकारिता में सहकार" पहल के अंतर्गत समस्त सहकारी समितियों एवं सदस्यों के बैंक खाते, राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की शाखाओं में संधारित करते हुए इन्ही बैंक खातों के माध्यम से व्यवसायिक गतिविधियां किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

9. <u>राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL)</u>

प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की 1200 से अधिक सहकारी समितियों द्वारा सदस्यता प्राप्त कर ली गई हैं।

10. <u>राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड</u> (NCOL)

प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड की 1268 से अधिक सहकारी समितियों द्वारा सदस्यता प्राप्त कर ली गई हैं।

11. <u>भारतीय बीज सहकारी संघ लिमिटेड</u> (BBSSL)

प्रदेश स्तर पर भारतीय बीज सहकारी संघ लिमिटेड की 823 से अधिक सहकारी समितियों द्वारा सदस्यता प्राप्त कर ली गई हैं।

12. <u>समिति के सदस्यों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड का प्रदाय</u>

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से 64,411 रूपे डेबिट कार्ड एवं 11,962 रूपे केसीसी कार्ड जारी किये जा चुके है।

13. <u>एनसीडीसी के माध्यम से सभी अन्कवर्ड विकासखंडों में पैक्स में 1100 एफपीओ का गठन</u>

एनसीडीसी से प्राप्त आवंटन पश्चात 23 अन्कवर्ड विकास खंडों में 23 एफपीओ का गठन।

14. <u>राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) और जिला सहकारी विकास समिति (DCDC)</u>

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के विभिन्न आयामों का पर्यवेक्षण राज्य स्तर पर SCDC और जिला स्तर पर DCDC के माध्यम से निरंतर किया जा रहा है।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग